भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2733

7 अगस्त, 2024 को उत्तर देने के लिए

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजनाएं

†**2733. श्री के. ई. प्रकाश:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस समय चल रही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) तमिलनाडु राज्य में स्थित संस्थानों में कार्यरत बड़ी संख्या में शोधकर्ताओं को मंत्रालय के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों के तहत सहायता प्रदान की गई है। पिछले तीन वर्षों (2021-23) में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने तमिलनाडु स्थित विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संगठनों में काम कर रहे अनुसंधानकर्ताओं की 21 परियोजनाओं को लगभग 5.38 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सहायित किया है। ये परियोजनाएं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों जैसे ब्रह्माण्ड विज्ञान, फोटोनिक्स, लिथियम धातु बैटरी, पदार्थ विज्ञान, वन्यजीव जीव विज्ञान, वायरल प्रोटीन, माइक्रो-प्लास्टिक आदि को कवर करती हैं। वर्तमान में, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सात अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं तमिलनाडु में विभिन्न चरणों में कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ख) एवं (ग): मंत्रालय तमिलनाडु सहित पूरे भारत में स्थित अपने विभागों, स्वायत्त संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं, सेमिनार, अध्येतावृत्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उन्नत स्कूल, आदान-प्रदान और प्रभावन दौरे, उन्नत सुविधाओं तक पहुंच आदि शामिल हैं। जर्मनी, बेलारूस, इजराइल और ताइवान में वैश्विक रूप से स्वीकृत कुछ अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ नई सहयोग सहलग्नता को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले वर्ष में विकसित करके औपचारिक रूप दिया गया। इन प्रयासों से तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में स्थित अनुसंधान संस्थानों की गतिविधियों में तीव्र वृद्धि हुई है।

*****